

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०-1/छात्रवृत्ति-रा०यो०-प्री-मैट्रिक-06/2010- 20

पटना, दिनांक- 28/03/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल ₹0 32951.02 लाख (₹0 तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यावन लाख दो हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत अतिरिक्त योजना उद्व्यय में ₹0 32951.02 लाख (₹0 तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यावन लाख दो हजार) मात्र प्राप्त हुआ है। उक्त योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में उक्त राशि का बजट उपबंध भी किया गया है। उपबंधित राशि संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा कूट संख्या-3401-विपत्र कोड-P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड, BCW-5461

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4- साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान उन्हीं छात्र/छात्राओं को किया जाय जिनकी कक्षा में 75% या उससे अधिक उपस्थिति हो, एवं उन्हें पूर्व वर्ष की निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाय। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा-निर्देश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर मार्च के अन्त में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वार्षिक उपयोग दिनांक-31.03.2017 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

